

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
स्तर-1, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 25 जुलाई, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के अन्तर्गत गौलीखाल से किनगोडीखाल के मध्य लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है की जनपद पौड़ी के अन्तर्गत गौलीखाल से किनगोडीखाल के मध्य लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु रु० 0.50 लाख (रु० पच्चास हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय करने की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष प्रचलित व्यवस्था एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप प्रारम्भिक आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से आगणन की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करते हुये स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये सक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कराली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रविलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

5- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरित्ता के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टेंडर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेंडर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुकूलन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।



प्रदीप सिंह रावत

- 7- कार्य की गुणवत्ता एवं सन्तुष्टता हेतु सम्बन्धित अधिकासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किसी अन्य दफत से धनराशि रवीकृत हुई हो तो उसका दिवसन शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य भवन-13-पूछ आवात योजना-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संस्था-यू0आं0-673(1) XXVII (2)/08 दिनांक 25 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

संख्या- 2489 (1)/III(2)/08-03(मु0मं0घो0)/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा प्रथम औराय मेडर्स बिल्डिंग, मांजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 4- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 8- लोक निर्माण विभाग, अनुभाग-1/3, उत्तराखण्ड शासन/ गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

प्रदीप सिंह रावत

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

d